Testwale Current Affairs PDF

Current Affairs search results for tag: economyfinance

1. [illegible] (Oct. 26, 2022)

[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] 24 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]//[illegible], [illegible]

[illegible]-[illegible]/[illegible]

[illegible]

[illegible] 1999 [illegible]

[illegible] 1999 [illegible] 2000 [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible]/**IRDAI**: [illegible]

2. [illegible] (Oct. 25, 2022)

[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] 995 [illegible] 999 [illegible] 1 [illegible] 10 [illegible] 100 [illegible]

[illegible]?

[illegible] 10 [illegible] 100 [illegible]

[illegible]

[illegible] **?**

[illegible] 10 [illegible] 100 [illegible]

10 [illegible] 100 [illegible]

[illegible]**?**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 22 [illegible]

[illegible]

[illegible] 1875 [illegible]

[illegible]

2017 [illegible]

[illegible]

3. [illegible] **(Oct. 25, 2022)**

CCI fines Google Rs 936 crore

[illegible] **936.44** [illegible] 1,337.76 [illegible]

[illegible]

[illegible] ?

[illegible]

4. [illegible] (Oct. 25, 2022)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (**सीसीआई**) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत, अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी ।

इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।

आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना ।
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और
- व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

सीसीआई के सदस्य

इसमें **कुल 7 सदस्य** होते हैं; एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य।

सदस्यों को सरकार द्वारा **पांच साल** के लिए नियुक्त किया जाता है और वे नियुक्तियों के लिए फिर से पात्र होते हैं।

हालाँकि सदस्यों को **पैंसठ वर्ष की आयु** प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होना पड़ता है।

CCI के पहले अध्यक्ष: **धनेंद्र कुमार**

मुख्यालय: **नई दिल्ली**

फुल फॉर्म

सीसीआई/CCI: कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया

5. कैशे और आईआरसीटीसी ,आईआरसीटीसी ऐप पर बुक किए गए टिकट के लिए अभी यात्रा करें बाद में भुगतान करें सुविधा शुरू करेंगे (Oct. 24, 2022)

[CASHe and IRCTC launch pay later facility](#)
[ऑनलाइन ऋण देने वाली ऐप्स](#) **कैशे** (**CASHe**) ने आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर '**ट्रैवल नाउ पे लेटर**' ('अभी यात्रा करें बाद में भुगतान करें') भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस सुविधा के तहत आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से रेल टिकट बुक करने वाला व्यक्ति अपना टिकट बुक कर सकता है और बाद में तीन से छह महीने में समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में टिकट राशि का भुगतान कर सकता है। यह सुविधा वेतनभोगी पेशेवरों के लिए उपलब्ध होगी।

डिजिटल लेंडिंग और कैश

यहां कैश द्वारा ऋण प्रदान नहीं किया जाता है। यह एक उधार सेवा प्रदाता है जो आरबीआई और उधारकर्ता द्वारा विनियमित बैंकों और एनबीएफसी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ऋण **धनिक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड** द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह आरबीआई द्वारा विनियमित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)

है। कैशे सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ऋणदाता और उधारकर्ता को एक साथ ऑनलाइन मिलाता है।

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

आईआरसीटीसी की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी।

इसका मुख्यालय: **नई दिल्ली**

इसके व्यवसाय है;

- रेलवे स्टेशन पर खानपान और आतिथ्य
- इंटरनेट टिकटिंग
- यात्रा पर्यटन
- डिब्बाबंद पेयजल (रेल नीर)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: **रजनी हसीजा**

6. म्यांमार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्टेड देशों के सूची में उत्तर कोरिया और ईरान के साथ शामिल (Oct. 22, 2022)

Financial Action Task Force

अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने म्यांमार को "ब्लैक लिस्ट" में डाल दिया है और सदस्यों से म्यांमार में व्यापारिक संबंधों और लेनदेन में **ड्यू डिलिजेंस** बढ़ाने का आह्वान किया है। म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया के बाद एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट" की सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया है ।

मनी लॉन्ड्रिंग(धन शोधन) एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपराधिक गतिविधियों जैसे तस्करी, संगठित अपराध आदि के माध्यम से उत्पन्न धन को कानूनी वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि इन धन की उत्पत्ति को छिपाया जा सके।

एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट

जिन देशों में कमजोर एंटी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट नियामक ढांचा हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है । यह एक तरह से से उस देश के लिए एक चेतावनी होती है की वह अपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रणाली में सुधार करे ।

ब्लैक लिस्ट

जो देश कार्रवाई करने से इनकार करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाते हैं, उन्हें **कॉल फॉर एक्शन के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट** में डाल दिया जाता है। फिलहाल ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार इस सूची में हैं।

म्यांमार के लिए इस कदम का प्रभाव

म्यांमार के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंकों जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

विदेशी निवेशक और वित्तीय संस्थान म्यांमार और उसके वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों के साथ लेन-देन करने से बचेंगे।

अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ व्यापार करने की लागत म्यांमार के लिए बढ़ जाएगी जो इसके व्यापार और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां म्यांमार की रेटिंग को डाउनग्रेड करेंगी जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में म्यांमार की कंपनियों और बैंकों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि उन्हें पैसे उधार लेने के लिए बहुत अधिक ब्याज दरों का भुगतान करना होगा।

एफएटीएफ

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)की स्थापना 1989 में 7 देशों के समूह की सिफारिश पर की गई थी।

एफएटीएफ का कार्य

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।
- यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जो एक अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।
- एफएटीएफ ,मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों की समीक्षा करता है और नए जोखिमों को संबोधित करने के लिए अपने मानकों को लगातार मजबूत करता है।
- भारत का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून, **धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002** एफएटीएफ के मानकों पर आधारित है।
- एफएटीएफ के कुल सदस्य देश वर्तमान में **39 हैं।**
- भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना।

मुख्यालय: **पेरिस, फ्रांस**

अध्यक्ष : **टी राजा कुमार** (सिंगापुर नागरिक)

7. केंद्र सरकार और उसके विभाग द्वारा 10 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने रोजगार मेला का शुभारंभ किया (Oct. 22, 2022)

PM Modi launches Rozgar Mela

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले महीनों में 10 लाख रोजगार देने के लिए वस्तुतः **22 अक्टूबर** 2022 को **रोजगार मेला** का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के तहत नियुक्ति पत्र दे रही है।

समारोह के दौरान, 75,000 नवनियुक्त नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये नई भर्तियां केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगी।

नियुक्त व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे। समूह - ए, समूह - बी (राजपत्रित), समूह - बी (अराजपत्रित) और समूह - सी।

जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं।

8. रूसी गज़प्रॉमबैंक ने यूको बैंक में खोला खाता (Oct. 22, 2022)

Russian Gazprombank opens account with UCO bank

रूसी बैंक **गज़प्रॉमबैंक** ने कोलकाता स्थित **यूको बैंक** के साथ एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोला है। यूको बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) से भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटाने के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक है ।

यूको बैंक को क्यों चुना गया है

गज़प्रॉमबैंक, रूस में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसे दुनिया के सबसे बड़े गैस उत्पादक और निर्यातक गज़प्रोम द्वारा स्थापित किया गया है। गज़प्रोम को संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसे केवल क्षेत्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका उन कंपनियों या बैंकों पर प्रतिबंध लगाता है जो इसकी प्रतिबंध सूची में शामिल कंपनियों के साथ सौदा करते हैं। एक कंपनी जो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करती है, उसे दुनिया में व्यापार करना बहुत मुश्किल हों जाता है क्योंकि विश्व वित्तीय बाजार में अमेरिकी वित्तीय संस्थानों का वर्चस्व है।

यूको बैंकों की न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है और अगर संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर प्रतिबंध भी लगा दे तो इसके व्यवसाय पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इससे पहले जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उस समय भी , ईरान के साथ व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा यूको बैंक को चुना गया था।

विशेष वोस्ट्रो खाता

भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय रुपये को बढ़ावा देने की इच्छुक है। 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (निर्यात और आयात) के निपटान के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाते के उपयोग की अनुमति दी थी ।

इस तंत्र के तहत किसी भी देश की बैंक ,एक भारतीय बैंक के साथ एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलेंगे। मान लीजिए कि भारतीय बैंक यूको बैंक है और विदेशी देश रूस है और रूसी बैंक गज़प्रॉमबैंक है। एक भारतीय व्यवसायी

एक रूसी कंपनी से 200 रुपये मूल्य कीगैस खरीदता है। यह राशि यूको बैंक में गज़प्रॉमबैंक के खाते में जमा की जाएगी।

उसी समय एक रूसी कंपनी एक भारतीय कंपनी से 125 रुपये की चाय खरीदती है।

यहाँ पर यूको बैंक के पास गजप्रोम बैंक खाते में जमा किए गए 200 रुपये से 125 रुपये काट लिए जाएंगे।

आरबीआई का कहना है कि शेष 75 रुपये की राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है।

यहां सारा कारोबार भारतीय रुपये में हो रहा है और बंदोबस्त भी भारतीय रुपये में हो रहा है।

नोस्ट्रो और वोस्त्रो बैंक खाता क्या है

नोस्ट्रो और वोस्त्रो को समझने के लिए मुख्य शब्द का अर्थ जानना ज़रूरी है।

लैटिन भाषा में नोस्ट्रो का अर्थ **हमारा** और वोस्त्रो का अर्थ **आपका** होता है।

नोस्ट्रो खाता

यह एक बैंक खाता है जो एक विदेशी बैंक के साथ एक बैंक द्वारा विदेशी देश की मुद्रा में खोला जाता है।

वोस्ट्रो खाते

यह वह बैंक खाता है जो एक बैंक किसी विदेशीबैंक का खाता अपने पास रखता है और जो स्थानीय मुद्रा में होता है।

व्याख्या

नोस्ट्रो और **वोस्ट्रो** खाते एक ही बैंक खाते हैं लेकिन इसे समझाने के लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंदन जाता है और लंदन में एचएसबीसी बैंक की शाखा में खाता खोलता है। खाता खोलते समय एसबीआई को अपने खाते में कुछ पैसे जमा करने होते हैं।एसबीआई अपने खाते में पैसा पाउंड स्टर्लिंग में करेगा जो ब्रिटेन की मुद्रा है।

एसबीआई, एचएसबीसी को कहेगा कि "**हमारा**" खाता आपके पास है। एचएसबीसी, एसबीआई से कहेगा कि "**आपका**" खाता हमारे पास है।

यह एक ही बैंक खाता है लेकिन एचएसबीसी और एसबीआईइसका वर्णन करने के लिए अलग-अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।

यहाँ एसबीआई ने **हमारा** शब्द का प्रयोग किया है, इसका अर्थ है कि एचएसबीसी वाला एसबीआई का खाता एक **नोस्ट्रो** खाता है।

एचएसबीसी ने '"**आपका**' शब्द का प्रयोग किया है इसलिए एचएसबीसी के लिए एसबीआई खाता **वोस्ट्रो** खाता है।

यूको बैंक

[illegible] 6 [illegible] 1943 [illegible]

1969 [illegible]

1985 [illegible]

[illegible]

[illegible]: **[illegible]**

[illegible]: **[illegible]**

[illegible]: **[illegible]**

9. [illegible] (Oct. 22, 2022)

President of Indian Bank Association

[illegible] 21 [illegible] 2022 [illegible] 2022-23 [illegible] 2021-22 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: **[illegible]**

[illegible]: **[illegible]**

10. पीएमएवाई- सीएलएसएस के तहत एचडीएफसी को मिला सर्वश्रेष्ठ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पुरस्कार (Oct. 21, 2022)

best housing finance company award

भारत की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड को **राजकोट, गुजरात** ,में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में सरकार की प्रमुख योजना - प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री **हरदीप सिंह पुरी** ने राजकोट में एचडीएफसी लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक और प्रमुख सीएलएसएस और किफायती आवास संजय जोशी को पुरस्कार से सम्मानित किया।

जून 2016 में पीएमएवाई के तहत सब्सिडी योजना शुरू होने के बाद से, एचडीएफसी ने इस योजना के तहत 3.13 लाख से अधिक ग्राहकों को 67,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है।

यह तीसरी बार है जब एचडीएफसी को यह पुरस्कार दिया गया है।

जुलाई 2018 में, एचडीएफसी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय वर्ग (एलआईजी) खंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक ऋण संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया था ।

मार्च 2019 में, एचडीएफसी को पीएमएवाई - अफोर्डेबल हाउसिंग अवार्ड्स 2019 में पीएमएवाई - सीएलएसएस के लिए 'सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान' से सम्मानित किया गया था।

एचडीएफसी लिमिटेड को 1977 में एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी) के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर है।

एचडीएफसी लिमिटेड का मुख्यालय : **मुंबई**

एचडीएफसी के अध्यक्ष **दीपक पारेख** हैं।